काफी समय से रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इतने लंबे समय से पद के रिक्त होने के क्या कारण हैं, तथा इस नियुक्ति के संबंध में क्या विवाद है;

(ग) क्या महानिदेशक के कार्य-निर्वहन हेतु मौजूदा अधिकारी अर्हताओं संबंधी सभी मानदंड पूरा करते हैं, यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्ति की गई है; और

(घ) क्या सरकार अर्हता/अनुभव के आधार पर तथा विवाद रहित नियुक्ति करेगी यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद 31 मार्च, 1993 को पिछले पदधारी की सेवा-निवृत्ति के बाद से रिक्त पड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई भी अधिकारी तत्कालीन भर्ती नियमावली के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया गया। पद को विज्ञापित किया गया था और इसे सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय विभागों के बीच परिचालित भी किया गया था। इस प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति भी गठित की गई तथा प्राप्त किए गए आवेदन संघ लोक सेवा आयोग को अग्रसारित किए गए। चूंकि, चौथे वेतन आयोग के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के वेतनमान में संशोधन हो गया और चूंकि भर्ती नियम पूर्व वर्षों के थे, अतः संघ लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया कि भर्ती नियमों को संशोधित करना होगा तथा इनके संशोधित हो जाने तक आयोग के साथ मिलकर भर्ती के तरीके तय कर लिए जाएं। आयोग के इस निर्णय को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कोई भर्ती नियम नहीं हैं। इस अंतराल में, सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार संभालने के लिए अपर महानिदेशक (प्रशासन) को निर्देश दिया। भर्ती के नये तरीके के लिए आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, जिसके अधीन अर्हताओं तथा अनुभव के वर्षों में संशोधन किया गया है, ताकि इसमें अधिकाधिक संस्थाओं एवं उच्च अर्हता वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित भर्ती के नये तरीके के अनुसार अब पद को विज्ञापित भी कर दिया गया है। पात्र उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की अनुसंशा प्राप्त होने ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से उक्त पद भर दिया जाएगा। समुचित समन्वयन तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्य-भार अब सचिव, संस्कृति को सौंप दिया है।

Bogus Accounts opened in Mahila Samiriddhi Yojana

586. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what has been the progress of Mahila Samiriddhi Yojana, a saving scheme, aimed at upliftment of rural women, launched two years ago and what is the total number of beneficiaries as on date;

(b) whether it is fact that the incentives offerred by Postal Department to its employees on enrolment of new beneficiaries, work out more that the deposits made;

(c) whether the vigilance Department of Post & Telegraphs has discovered a large number of bogus accounts opened by postal employees just to derive the incentives; and

(d) whether Government would order an investigation in the matter and revamp the scheme to prevent diversion of incentives to wrong persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVARAJESWARI): (a) The scheme of Mahila Samiriddhi Yojana (MSY)) was launched on 2 October, 1993. As on 31 October, 1994,

59.23 lakh rural women have opened their accounts.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

Diamond mining contract

587. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether a diamond mining contract is being considered between Madhya Pradesh Government and the MNC conglomerate De Beers for prospecting of diamonds in Raipur area.

(b) whether any Memorandum of Understanding has been signed in this regard and if so, whether Hindustan Diamond Corporation (subsidiary of De Beers in India) is one of the signatories;

(c) whether Government are aware that De Beer were asked to pack off by the Angolan Government after the former had not exploited the contracted area for more than 10 years to block diamond production and thus to control the trade; and

(d) whether it is a fact that Minerals and Metals Trading Corporation of India jointly with National Mineral Development Corporarion (NMDC) is scouting for contracts abroad for diamond mining especially in Vietnam, Myanmar and Cambodia and if so, why in the first place MNC like De Beers are being entertained in preference to indigenous technology and capabilities for exploiting our own diamond resources?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Government have received a proposal from the Government of Madhya Pradesh for grant of a prospecting licence in favour of M/s. De Beers.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Diamond mining possibilities in Vietnam, Myanmar and Cambodia are yet to be proven. However, proven deposits of coloured stones, particularly rubies, do exist. Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) and National Mineral Development Corporation (NMDC) have made proposals to Vietnam but these are all in the preliminary stages of discussion. However, the proposal of Government of Madhya Pradesh is a sequeel to global tenders for prospectting licence and the proposal of the State Government is based on techno-economic evaluation of the responses received by them.

अपरिष्कृत और तैयार उत्पादों पर अलग अलग आयात शुल्क

588. **श्री अजीत जोगी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत तांबे, सेमिस तथा तैयार मालक के लिए अलग-अलग आयात शुल्क संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) निर्णय लेने में विलम्ब का तांबे सेमिस और संबंध एक्कों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ङ) क्या तांबे सेमिस तथा तैयार उत्पादों के आयात से कर्मकारों की छंटनी होगी ; और

(च) यदि हां, तो सरकार कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर इस मामले में सरकार के विचार जाहिर करना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।